2021-22 चीनी मौसम में भारत में गन्ना मूल्य बकाया 5,775 करोड़ रुपये बढ़ा

चीनी मौसम 2021-22 (अक्तूबर-सितंबर) में किसानों का गन्ना बकाया पिछले मौसम से 5,775 करोड़ रुपये बढ़ा है, जिसमें उत्तर प्रदेश में किसानों की बकाया राशि सबसे अधिक है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग (सी ए सी पी) द्वारा अपनी 'गन्ने के लिए मूल्य नीति: 2023-24 चीनी मौसम' में संकलित आंकड़ों के अनुसार, 30 सितंबर, 2022 तक, संचयी गन्ना मूल्य बकाया 8,380 करोड़ रुपये था, जिसमें से 2021-22 मौसम का बकाया 5,910 करोड़ रुपये है, जो कि 2020-21 मौसम के लिए 135 करोड़ रुपये से काफी अधिक है — 4,277.7% की वृद्धि।

सी ए सी पी ने कहा कि सभी राज्यों में, 2021-22 के दौरान कुल गन्ना मूल्य बकाया का 66.7% (3,945 करोड़ रुपये) उत्तर प्रदेश में है, इसके बाद गुजरात में 999 करोड़ रुपये (16.9%), महाराष्ट्र में 349 करोड़ रुपये (5.9%) और तमिलनाडु में 221 करोड़ रुपये (3.7%) है। संचयी गन्ना बकाया का बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश (47.7%), तमिलनाडु (20%), गुजरात (12.4%) और महाराष्ट्र (9.3%) में दर्ज किया गया।

सी ए सी पी ने 2023-24 की गन्ना मूल्य नीति में उल्लेख किया है, "घरेलू और विश्व, दोनों बाज़ारों में अतिरिक्त उत्पादन और चीनी की कम कीमतों के कारण पिछले दो वर्षों के दौरान गन्ना मूल्य बकाया बढ़ रहा है। बकाया में वृद्धि और विलंबित भुगतान न तो किसानों और न ही चीनी मिलों के पक्ष में है।"

आयोग ने नीति में टिप्पणी की कि हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य गन्ने के लिए राज्य विवेचित मूल्य (एस ए पी) घोषित करते हैं, जो भारत सरकार द्वारा घोषित उचित और लाभकारी मूल्य (एफ़ आर पी) से अधिक है।

"चूंकि एस ए पी वैज्ञानिक रूप से निर्धारित नहीं है और एफ़ आ रपी के विपरीत चीनी की प्राप्ति से जुड़ा नहीं है, यह किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले गन्ने का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करता है। दूसरी ओर, एफ़ आ रपी चीनी की मूल प्राप्ति दर से जुड़ा हुआ है, जिसमें चीनी की अधिक प्राप्ति के लिए किसानों को प्रीमियम देय होता है। चूंकि चीनी मिलों को एस ए पी का

भुगतान करना आवश्यक है, जो एफ़ आर पी से अधिक है, इससे गन्ना मूल्य बकाया बढ़ जाता है, खासकर जब चीनी की कीमतें कम होती हैं," आयोग ने कहा।

सी ए सी पी ने कहा कि 2021-22 के दौरान, सभी चार राज्यों में एस ए पी में बढ़ोतरी की गई, जिससे पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड में एस ए पी और एफ़ आर पी के बीच अंतर बढ़ गया। 2023-24 की गन्ना मूल्य नीति में आयोग ने अपनी पिछली सिफारिश दोहराई है कि राज्य सरकारों को एस ए पी की घोषणा करने से बचना चाहिए।

आयोग ने कहा है कि यदि राज्य सरकारें एस ए पी को जारी रखना चाहती हैं, तो उन्हें प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डी बी टी) के माध्यम से सीधे गन्ना किसानों को एस ए पी और एफ़ आ रपी के बीच अंतर का भुगतान करना चाहिए और मिलों को अतिरिक्त बोझ उठाने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए।

गन्ना मूल्य बकाया का विवरण

राज्य	2019-20 तक (करोड़ रुपये)	2020-21	2021-22*		संचयी बकाया	
			करोड़ रुपये	प्रतिशत	करोड़ रुपये	प्रतिशत
उत्तर प्रदेश	42	11	3,943	66.7%	3,996	47.7%
गुजरात	36	0	999	16.9%	1,035	12.4%
महाराष्ट्र	317	111	349	5.9%	777	9.3%
तमिलनाडु	1,453	0	221	3.7%	1,674	20%
आंध्र प्रदेश	75	2	42	0.7%	119	1.4%
कर्नाटक	38	0	--	0	38	0.5%
छत्तीसगढ़	8	0	0	0	8	0.1%
हरियाणा	0	0	63	1.1%	63	0.8%
उत्तराखंड	205	0	34	0.6%	239	2.9%
पंजाब	31	7	58	1%	96	1.1%
तेलंगाना	0	0	0	0	0	0
बिहार	128	4	0	0	132	1.6%
अन्य राज्य	0	0	201	3.4%	203	2.4%
अखिल भारत	2,335	135	5,910	100%	8,380	100%

टिप्पणी: *चीनी मौसम 2021-22 के लिए 30 सितंबर, 2022 तक

स्रोत: चीनी और वनस्पति तेल निदेशालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय